माननीय वित्त मंत्री श्री चिदंबरम जी का संबोधन*

प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास के तीन खंडों के विमोचन के अवसर पर यहां उपस्थित होना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है।

इस अवसर पर, रिज़र्व बैंक के प्रमुख अनुसंधान प्रकाशनों में से एक ''वर्ष 2004-05 की मुद्रा और वित्त की रिपोर्ट'' का विमोचन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है।

इस रिपोर्ट में, 1999 से हर वर्ष किसी विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि बैंक के अन्य प्रमुख प्रकाशनों जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट और ''भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट'' में पुनरावृत्ति कम से कम हो।

इस रिपोर्ट का विषय नामतः ''इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल बैंकिंग इन इंडिया'' (भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास) इतिहास के खंडों के विमोचन के अवसर के बहुत ही अनुरूप है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिपार्ट में विश्व भर में केंद्रीय बैंकिंग के विकास के संदर्भ में भारत में केंद्रीय बैंकिंग के रूपांतरण को दर्शाने का प्रयास किया गया है । इसमें रिज़र्व बैंक के विविध कार्यों जैसे मौद्रिक और बाह्य क्षेत्र प्रबंध, संस्थाओं और वित्तीय बाजारों का विकास, लोक ऋण प्रबंध और बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षण का गहन विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की लोच को प्रदर्शित करती है जो कि तेजी से बदलते हुए घरेलू और बाह्य वातावरण को अपनाने की क्षमता प्रदान करती है।

वर्ष 1991 से वित्तीय क्षेत्र का सुधार आर्थिक नीतियों में उदारीकरण का अविभाज्य अंग रहा है। परिवर्तन लाने में भारतीय रिज़र्व बैंक ने न केवल बैंकिंग के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में, बल्कि उसे उपयुक्त योजना के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक और अंतरराष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशित ऋण प्रणाली के बजाय ऋण आबंटन की बाजार उन्मुख प्रणाली की तरफ जाने में एक साथ मिलकर कार्य किया है; हमने सरकार द्वारा ब्याज दर के निर्धारण की पिछली प्रणाली को तोड़ दिया है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक स्वचालित आधार पर सरकारी घाटे के लिए धन उपलब्ध नहीं कराता है। यह वर्ष इस दूसरे परिवर्तन से भी उल्लेखनीय है कि सरकार अपने लोक ऋण का प्रबंधन अपन हाथ में लेनेवाली है।

आज भारतीय रिज़र्व बैंक, देश का शीर्ष मौद्रिक प्राधिकारी होने के नाते, देश की मौद्रिक नीति, उसके विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध, बैंकिंग क्षेत्र में अपनी विकासात्मक भूमिका निभाने एवं मौद्रिक क्षेत्र के पर्यवेक्षक विनियामक के रूप में कार्य-निष्पादन के लिए मानकों का निर्धारण जैसे कई कार्य भी कर रहा है।

चूंकि हम 8 से 10 प्रतिशत की दर से उच्चतर वृद्धि की यात्रा पर निकल पड़े हैं इसलिए बचतों का उत्पादक निवेश में सक्षम आबंटन करने में वित्तीय क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। मुझे विश्वास है कि वित्तीय क्षेत्र बचत करनेवालों से संसाधनों को जुटाने और उन्हें सक्षम ढंग से सर्वाधिक उत्पादक कार्यों में लगाने जैसी चुनौतियों का सामना कर सकेगा।

मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता होती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियामक के रूप में, वित्तीय बाजारों के विकासकर्ता के रूप में और आम जनता को सेवा प्रदाता के रूप में अपनी कार्यपद्धति के सभी पहलुओं में अपना अंतिम लक्ष्य ग्राहकों का हित ही रखा है। वित्तीय समावेशन, क्रेडिट कार्ड की सेवाओं की गुणवत्ता, नोटों की मांग का प्रबंध एवं स्वच्छ नोट नीति के संबंध में अपने नवीनतम अनुदेशों और दिशानिदेशों में वित्तीय प्रणाली के माध्यम से, ग्राहक सेवा के इष्टतम स्तर को ध्यान में रखा गया है। मुझे विश्वास है कि भारतीय रिज़र्व बैंक आनेवाले वर्षों में भी ग्राहकों पर अपना ध्यान और अधिक केन्द्रित करेगा ।

वित्तीय क्षेत्र की उभरती चुनौतियों से निपटते समय कुछ और मुद्दे हैं जिन्हें मध्यावधि में सुलझाया जाना जरूरी है। अक्सर यह भी देखने में आया है कि पूंजी बाजार के कुछ खिलाड़ी यदि कोई आपराधिक खेल खेलते हैं तो इसका पता पूंजी बाजार में कार्यरत संस्थाओं से चल जाता है। यद्यपि ऐसे उदाहरण बहुत व्यापक नहीं हैं, फिर भी यह जरूरी है कि देश के केंद्रीय बैंक की संस्थागत और विनियामक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी हो जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का देश के पूंजी बाजार में विश्वास बना रहे। वित्तीय क्षेत्र के शेष संरचनात्मक ढांचे में भी परस्पर संबंधों का बनाया जाना ज़रूरी है जो कि अभी तक पूर्ण रूप से विनियमित नहीं है। इसके अलावा, देश के अत्यधिक वित्तीय खुलेपन के अपने लाभ और जोखिम भी हैं। उन जोखिमों से उदारीकृत ढांचे के अंतर्गत निबटना होगा।

* भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में 18 मार्च 2006 को मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट 2004-05 के विमोचन के अवसर पर ।

जैसा कि रिपोर्ट में लिखा गया है, रिज़र्व बैंक बदलती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप ही लगातार विकास कर रहा है। जैसे-जैसे अर्थ व्यवस्था में और अधिक खुलापन आता जा रहा है, हमें व्यापक स्तर पर इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा । इसलिए मैं विश्वासपूर्वक यह आशा कर सकता हूं कि रिज़र्व बैंक ने पिछले 70 साल में निरंतर परिवर्तन की जो राह दिखाई है उसे वह अगले 70 साल में और उससे आगे भी जारी रखेगा।